Mr. Speaker: No question, no clarification. This has become a recurring matter. If any hon. Member wants any further clarification on a statement made in the House, this is not the way.

Shri Hem Barua: Whether the persuasive attempts of the police....

Mr. Speaker: Order, order. I am not going to allow. Let us proceed. Shri Dasappa may move his motion.

12.17 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

Estimates Committee

Shri Dasappa (Bangalore): Sir, I beg to move:

> "That the Members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (3) of Rule 254 read with sub-rule (1) of Rule 311 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, one Member from among themselves to serve as a member of the committee on Estimates for the unexpired portion of the term ending on 30th April, 1960, *vice* Shri Mathuradas Mathur, resigned."

Mr. Speaker: The question is:

> "That the Members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (3) of Rule 254 read with sub-rule (1) of Rule 311 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, one Member from among themselves to serve as a member of the committee on Estimates for the unexpired portion of the term ending on 30th April, 1960, vice Shri Mathuradas Mathur, resigned."

The motion was adopted.

12.18 hrs.

STATUTORY RESOULTION *RE*: SUGAR (SPECIAL EXCISE DUTY) ORDINANCE AND SUGAR (SPECIAL EXCISE DUTY) BILL.

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरे नाम पर है, उसको सब से पहले मैं पढ़ देना चाहता हूं और ऐसा करने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

> "This House disapproves of the Sugar (Special Excise Duty) Ordinance, 1959 (Ordinance No. 3 of 1959) promulgated by the President on the 25th October, 1959."

श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव मैंने पढ़ा है.....

The Ministr of Revenue and Civil Expenditure (Dr. B. Gopala Reddi): Sir, I may be allowed to move my Bill so that both the Bill and the Resolution may be considered simultaneously.

Mr. Speaker: Normally I allow the Resolution to be moved. The hon. Member in whose name the Resolution stands moves his resolution and makes a speech. But there is a connected matter, a Bill for consideration and passing. If the House agrees I will allow the hon. Member to formally move his resolution and allow him an opportunity to speak both on the motion for consideration of the Bill and his resolution; otherwise, he may not get a chance to speak on the Bill. I will take it that he has moved his motion. I shall now place it before the House. Motion moved:

> "This House disapproves of the Sugar (Special Excise Duty) Ordinance, 1959 (Ordinance No. 3 of 1959) promulgated by the President on the 25th October, 1959."

I will allow the hon. Member to speak after the other motion is made.

Shri Bimal Ghose (Barrackpore): If this resolution is approved, the other motion will not come at all.

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam): They are confident that it would not be passed.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): Sir, on previous occasions when such resolutions were moved disapproving certain ordinances passed when the Parliament was not in session the procedure adopted was to allow the hon. Member concerned to move his resolution and make a speech after which the Minister concerned was asked to move his motion for consideration of the Bill followed by a discussion in the House.

Mr. Speaker: I have no objection to adopt either course. If it is the desire of the House that this resolution be disposed of first, we will take up the Bill later.

Shri Rane (Buldana): In that case a time limit will have to be fixed for the resolution. In all five hours have been allotted for both these motions.

Mr. Speaker: The Business Advisory Committee has fixed five hours for consideration of both these things. Hon. Members are not going to vote for or against merely because another motion has been made. Let us adopt this practice. Let hon. Members address themselves to both these matters and vote separately.

Dr. B. Gopala Reddi: I beg to move:

> "That the Bill to provide for the imposition of a special duty of excise on certain sugar, be taken into consideration."

May I speak on the motion?

Mr. Speaker: I shall place this motion before the House and I shall allow him to make a speech later on. Motion moved:

> "That the Bill to provide for the imposition of a special duty of excise on certain sugar, be taken into consideration."

श्री खुशवक्त राय : श्रीमन् मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में पिछली बार १४ अगस्त को शूगर के मामले में वाद-विवाद हुआ था और उस वाद-विवाद के बाद ही हमारे खाद्य मंत्रालय में परिवर्तन हुआ, यहां तक कि हमारे मंत्री जी भी बदल गए। हमारे माननीय मंत्री जी के बदलने के साथ ही साथ बहुत सी और भी चीजें बदलीं, जैसे मकान बदल गया, मंत्रालय के कर्मचारी बदल गए, मंत्रालय की मेज़ कुर्सियां बदल गईं, मंत्रालय के टेलीफोन नम्बर इत्यादि बदल गए। ये सब चीजें तो बदलीं परन्तु सरकार की वह अभागी नीति जिसके कारण गन्ने की काश्त करने वालों का शोषण होता है, गन्ने की काश्त करने वालों का गला घोंटा जाता है, नहीं बदली। श्रीमन्, जब वर्तमान मंत्री जी नियुक्त हुए थे, तब मुझे उन से बड़ी बड़ी आशायें थीं और मैं समझता था कि माननीय मंत्री के पदारूढ़ होने के बाद गन्ने के काश्तकारों को भी कुछ अच्छा लाभ मिलेगा परन्तु मुझ को तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि खाद्य मंत्रालय जो है, वह एक लीक में पड़ गया है, एक रट में पड़ गया है और उस रट में से किसी के लिए भी जो उसमें पड़ जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। एक दोहा है जो श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> लीकै लीक चलती है कापर कूर
> कपूत
> लीक छाड़ि के चलति है सापर सूर
> सपूत

श्रीमन्, मुझ को तो यह आशा थी कि हमारे मंत्री जी अपने को सपूत सिद्ध करेंगे परन्तु वह भावना जो मेरी थी, वह गलत निकली। मुझ को अफसोस के साथ आज फिर यह कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय की तथा खाद्य मंत्रालय की जो नीति शूगर के मामले में है और जो बर्ताव उसका गन्ने

के काश्तकारों के साथ है, वह मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है।

अब आप देखिये, श्रीमन कि यह आर्डिनेंस, यह अध्यादेश २५ अक्तूबर को निकाला गया था और १६ नवम्बर को यह सदन बैठने वाला था। सदन कब तक बैठने वाला है, इसका सभी को बहुत पहले मालूम था। इतना होने पर भी इस आर्डिनेंस को निकाला गया, इसकी क्या वजह है ? यह भी आपको मालूम है, श्रीमन्, कि इससे बहुत पहले से जो नीति चली आई थी, जैसे शूगर एक्सपोर्ट प्रामोशन आर्डिनेंस निकाला गया था जिसे कि पुराने मंत्री जी ने निकाला था, उससे वर्तमान मंत्री महोदय ने भी समझ लिया कि हां यह रास्ता तो खुला हुआ है, एक अध्यादेश निकाल दो और अध्यादेश निकाल दिया गया और सदन की कोई परवा नहीं की गई। अब आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अध्यादेश निकालने से क्या होता है। सदन जब बैठा होता है, तब जो इस तरह की बात होती है वह सदन के सामने आती है और उस में कुछ संशोधन चाहे तो हो सकता है। परन्तु जब अध्यादेश जारी कर दिया जाता है और बाद में जब उसको स्वीकृति के लिए इस सदन के सामने पेश किया जाता है तो यह एक मान-प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है सरकार के लिए कि जब अध्यादेश बना है तो उसी तरह से विधेयक भी पास हो। तो अगर यह विधेयक के रूप में हमारे सामने आता तो यह सम्भव था कि इस में कोई ऐसा संशोधन हो जाता जिससे कि काश्तकारों को कुछ फायदा पहुंच जाता। यह बात हो सकती थी। परन्तु जब अध्यादेश बन गया, आर्डिनेंस जारी हो गया तब तो यह सरकार के लिए मान-प्रतिष्ठा की बात हो गई और वह चाहेगी कि जिस तरह का अध्यादेश बना है उसी तरह का विधेयक पास हो जाये।

हमारी सरकार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि हमारा प्रजातांत्रिक राज्य है, हमारे यहां डेमोक्रेसी है। परन्तु आज जब हम आर्डिनेंस के ज़रिये से राज करना चाहते हैं, कोई भी बात हो, छोटी से छोटी बात भी चाहे क्यों न हो उसके लिए इस बात का फ़ायदा उठा लिया जाता है कि सदन बैठा हुआ नहीं है और आवश्यकता हो या न हो, अध्यादेश निकाल दिया जाता है, तो इससे प्रजातंत्र का कहां तक मेल बैठता है, यह सोचने वाली बात हो जाती है। आपके ज़रिये, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अध्यादेश द्वारा हुकूमत करने की जो नीति है, उसको बदला जाना चाहिए।

अब श्रीमन्, जो अध्यादेश निकला है, उसके ऊपर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। सरकार की तरफ से एक बिल भी पेश किया गया है जिस का नाम है शूगर (स्पेशल एक्साइज़ ड्यूटी) बिल। इसके स्टेटमेंट आफ ऑबजैक्ट्स एंड रीज़ंस जो दिये गये हैं, उसमें तीन बातें कही गई हैं। पहली बात तो यह कही गई है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाना, जब गन्ने का मूल्य बढ़ाना है इसलिए शूगर के दाम भी बढ़ाने होंगे और तीसरे शूगर के जब दाम बढ़ाने हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह ड्यूटी लगा दी जाये। ये तीन बातें हैं, जिन पर कि मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। यही तीनों बातें अध्यादेश में हैं और यही तीनों बिल के आबजैक्ट्स एंड रीज़ंस में भी हैं। एक के बाद दूसरी बात आती है। पहले गन्ने का मूल्य बढ़ाना, गन्ने के मूल्य बढ़ाने के कारण शूगर का मूल्य बढ़ाना और शूगर के मूल्य बढ़ाने के कारण एक्साइज़ ड्यूटी का लगना।

जहां तक गन्ने के मूल्य बढ़ाने का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९५७ से ही जब से कि यह सदन शुरू हुआ यानी दूसरी लोक सभा शुरू हुई, तब से ही बराबर इस बात की चर्चा यहां होती रही है और यह मांग की जाती रही है कि गन्ने के दाम बढ़ने चाहियें। १८ दिसम्बर,

[श्री खुशवक्त राय]

१९५८ को जब इस सदन ने इस मामले पर बहस की थी उस समय यह कहा गया था उन माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो उस समय थे, कि गन्ने के दाम नहीं बढ़ने चाहियें और वे इसलिए नहीं बढ़ने चाहियें क्योंकि शूगर की जो इन्डस्ट्री है, जो उद्योग है, वह बड़ी रेग्युलेटिड इंडस्ट्री है, बड़ा रेग्युलेटिड उद्योग है। उसके बाद आपने देखा कि इसी रेग्युलेटिड इंडस्ट्री में १९५९ में कितना रुपया चोर-बाजारी में कमाया गया। श्रीमन्, उनके लिए तो चोर-बाजारी करके रुपया कमाने की इजाजत और हमारे काश्तकारों का मुह बन्द, यह कहां का न्याय है। गन्ना वह पैदा करे, मेहनत वह करे और मूल्य उसी को सब से कम मिले। अब आप देखें कि मूल्य कौन मुकर्रर करते हैं। मूल्य मुकर्रर करने वाले व लोग हैं जिन्होंने कभी खेत का मुंह नहीं देखा है, जो खेत के नजदीक नहीं गये हैं, एक बिस्वा गन्ना भी नहीं बोया। आप मंत्रालय को देखें और मंत्रालय के ऊपर प्लानिंग कमिशन जो बैठा हुआ है, उसको देखें, उन दोनों को क्या अनुभव है, गन्ने की काश्त का ? कुछ भी नहीं है।

अब आप देखें कि गन्ने के सन् १९५२-५३ में क्या मूल्य निर्धारित किये गये थे और उसके बाद आज के दिन कितनी महंगाई बढ़ गई है। काश्तकार जिन चीजों को खरीदता है उन सब के दाम बढ़ गये हैं। कपड़ा वह खरीदता है, उसके दाम काफी बढ़ गये हैं। तम्बाकू वह खरीदता है, उस पर एक्साइज ड्यूटी काफी बढ़ गई है। ट्रैक्टर आते नहीं हैं और अगर आते भी हैं तो काफी महंगे मिलते हैं। इस तरह से आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उन सभी चीजों के, जिनको कि वह इस्तेमाल करता है, दाम बढ़ गये हैं। इतना होने पर भी गन्ने का मूल्य वही है। ऐसी सूरत में मुझे यह निवेदन करना है कि गन्ने का जो मूल्य मुकर्रर हुआ है वह कम है और वह इसलिए भी कम है कि गन्ना पैदा करने में जो लागत आती है वह एक रुपया बारह आने से अधिक आती है।

मुझे आश्चर्य होता है कि शूगर का मूल्य ठीक है या नहीं, यह जानने के लिए तो टैरिफ कमिशन की सलाह मांग ली जाती है और यह राय शायद पांच बार मांगी जा चुकी है लेकिन उससे यह राय कभी नहीं मांगी गई कि गन्ने का मूल्य क्या होना चाहिए। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि अभी हाल ही में यह मामला टैरिफ कमिशन के सामने गया था और उसने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि वह रिपोर्ट आज तक इस सदन के सामने रखी नहीं गई है। शायद उस पर सरकार ने अभी कोई फैसला ही नहीं किया है। रिपोर्ट आ गई है, यह मुझ को मालूम है। १९५० में जब टैरिफ कमिशन के सामने यह मामला गया था तो उसने कहा था कि २७ रुपये शूगर के दाम हों तब एक रुपया सात आने गन्ने के दाम होने चाहिएं। आज ४४-४५ रुपये मन शूगर बिक रही है और मिल का दाम जो है वह ३७ रुपये ७५ नये पैसे है और ऐसी सूरत में गन्ने का दाम क्या होना चाहिए इसका आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। सन् १९४७-४८ में जब शूगर का मूल्य ३५ रुपये ७ आने था उस समय गन्ने का मूल्य दो रुपया मन था और आज जबकि शूगर का मूल्य ३७ रुपया ७५ न० पै० है तो आप काश्तकार को क्या देते हैं ? एक बार यही सरकार तै कर चुकी है कि अगर ३५ रुपये ७ आने शूगर का मूल्य हो तो गन्ने का मूल्य दो रुपया मन होना चाहिए। यह तो मैं मानता हूं कि मंत्री जी के बदल जाने के बाद लोगों में यह समझ आई कि गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए, और गन्ने का मूल्य बढ़ाया भी गया, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। मैं समझता हूं कि अगर इस गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ता है तो उस का शूगर के उत्पादन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप देखिये कि आज के दिन गुड़ का क्या मूल्य है। गुड़ बीस रुपया मन

बिकता है । अगर इस के हिसाब से आप लगायें तो काश्तकार को गन्ने के १ रु० १० आ० लेने के बजाय गुड़ बनाने में अच्छा पड़ता पड़ता है । आप चाहते यह हैं कि शकर का उत्पादन बढ़े । जो स्टेटमेंट रखा गया है उस में आप ने कहा भी है कि शकर के उत्पादन को इन्सेन्टिव या प्रोत्साहन देने के लिए आप गन्ने के दाम बढ़ा रहे हैं । लेकिन अगर आप गन्ने की कीमत बढ़ा रहे हैं तो इस में गुड़ की कीमत का भी तो ख्याल कीजिये । अगर गुड़ की कीमत ज्यादा है और गन्ने की कीमत आप काश्तकार को कम दिलवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि काश्तकार मिल को गन्ना नहीं देगा । आप दूसरे मुल्कों की बात देखिये । आस्ट्रेलिया भी एक पूंजीवादी देश है । हम तो उस से जरा आगे बढ़ गये हैं परन्तु वह अभी पूंजीवादी देश है । उस में जो गन्ने का मूल्य है उस की तरफ आप ध्यान दीजिये । वहां पर चीनी का दाम ४२८ रु० ६ आ० ४ पाई प्रति टन है, और गन्ने का दाम ३१६ रु० ३ आ० मिलता है । लेकिन हमारे यहां क्या स्थिति है ? यहां पर चीनी का दाम ५६४ रु० ४ पाई है प्रति टन लेकिन गन्ने का मूल्य काश्तकार को ३५६ रु० १४ आ० मिलता है । दूसरे देशों को आप देखिये । पाकिस्तान में २ रु० १ आ० गन्ने का मूल्य है । इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि जो गन्ने का मूल्य होना चाहिए था वह आप नहीं कर पाये । मुझ को भी यही शिकायत है कि आज गन्ने का मूल्य २ रु० मन होना चाहिए था । लकड़ी भी हमारे शहर में २ या सवा २ रु० मन बिकती है । दिल्ली में आज मैं ने पूछा तो वह साढ़े तीन रुपया मन बिकती है । पर गन्ने की कीमत १ रु० १० आ० है । लकड़ी के पैदा करने में कोई मेहनत नहीं है, कोई सिंचाई नहीं होती, कोई गोड़ाई नहीं होती । परन्तु गन्ने की खेती में जो बोआई काश्तकार अक्तूबर में करता है उस में तो कम मेहनत होती है लेकिन जो जनवरी और फरवरी में बोआई करता है उसे उस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है । मई और जून की धूप लू वह अपने बदन पर लेता है । इतनी मेहनत कर के जब वह गन्ना पैदा करता है तो उस को मिल में उस की कीमत मिलती है १ रु० १० आ० मन, इसलिए कि इस में मिल मालिकों का फायदा है । मुझे बताया गया है कि जितनी शुगर मिल हिन्दुस्तान में हैं उन के मालिक ४६ परिवार हैं । उन ४६ परिवारों के फायदे के लिए गन्ने के जो काश्तकार हैं, जिन की तादाद करोड़ों की है, उनका शोषण किया जाता है ।

आज मैं आप को उत्तर प्रदेश की बात बतलाता हूं । वहां आज के दिन हड़ताल चल रही है । मैं भी वहां से कल ही आया हूं । मैं ने देखा कि गन्ने के काश्तकार गन्ना मिलों में नहीं लाते हैं । क्यों नहीं ला रहे हैं ? इसलिए नहीं ला रहे हैं कि वह समझदार हो गये हैं । हम उन से नहीं कहते हैं कि तुम गन्ना न लाओ लेकिन वह समझते हैं कि उन को गन्ने को उतने मूल्य पर नहीं देना चाहिए । इसलिए आज गन्ना मिलों में नहीं आ रहा है । जो ६६ मिलें हमारे उत्तर प्रदेश में हैं उनमें से ३७ ऐसी हैं जिनके कल बंद होने का खतरा है । कुछ तो मिलें ऐसी हैं जो पहले ही बन्द हो गई । मैं शरगांव से निकला तो वहां मुश्किल से ३ या ४ गाड़ियां कांटे पर थीं । गाड़ियां आई ही नहीं । १५ तारीख से हड़ताल शुरू हुई । मैं आप को शरगांव की मिसाल बतलाता हूं । १५ तारीख से हड़ताल शुरू होने वाली थी, लेकिन काश्तकार पहले से ही फैसला कर चुके थे कि गन्ना नहीं ले जाना है । १५ तारीख को उन्होंने मिल बन्द कर दिये लेकिन १६ तारीख को जब मिल चली तो वहां पर गन्ना ही नहीं था । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाइये क्योंकि उस का सम्बन्ध उस हड़ताल से है जो आज उत्तर प्रदेश में हो रही है । इस पर आप को विचार करना चाहिये और गन्ने का मूल्य बढ़ा देना चाहिए ।

[श्री खुशवक्त राय]

आप भी जानते हैं कि जो गन्ने का मूल्य है वह मुनासिब नहीं है। उन्होंने यह इच्छा भी प्रकट की है मिलों से कि अगर वह गन्ना अधिक लेना चाहते हैं तो उन को चाहिए कि वह गन्ने का मूल्य अपने आप बढ़ा दें हमारे मिल मालिक जो हैं, आप जानते हैं, वह कोई परोपकार के लिए मिल नहीं चला रहे हैं और आप के बिना आदेश दिये ऐसा नहीं हो सकता कि वह अपने आप दाम बढ़ा दें। आप आदेश देंगे तो वह मानेंगे क्योंकि मैं समझता हूं कि इस में उन का कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

Mr. Speaker: As I understand, the purpose of the Ordinance is this. In view of various representations that the sugarcane price has to be increased, the sugarcane price has been increased. It may or may not be sufficient according to some Members and others. But when once it has been increased, the ex-factory price of sugar also has been increased. Those people who purchase cane hereafter may not get more, but those who have already purchased sugarcane and have produced sugar will be able to sell it at a higher price that has been fixed. Why should they have the advantage? So, this is meant to mop off that excess profit which is a windfall today. The only point is whether the factory-owners should be allowed to take it away. Ultimately they will collect it from the consumers. So, why should the consumer lose the benefit of it or why should the excess money go into the hands of the factory-owners? That is the simple point. Why is the hon. Member going into other points?

श्री खुशवक्त राय : जो कुछ मैं कह रहा हूं उस का सम्बन्ध इन्हीं तीन बातों से है। आप देखिये कि शूगर एक्साइज ड्यूटी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए कि शक्कर का मूल्य बढ़ा। शुगर का मूल्य क्यों बढ़ा। इसलिए कि गन्ने का मूल्य बढ़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने का मूल्य कम बढ़ना, शुगर का मूल्य बढ़ना और एक्साइज ड्यूटी का लगना यह तीनों बातें गलत हैं। इस लिए गलत हैं कि जो गन्ने का मूल्य है उसे जितना बढ़ना चाहिए वह उतना नहीं बढ़ा। शक्कर का मूल्य बढ़ना नहीं चाहिए था . . . . .

The Minister of Food and Agriculture (Shri S. K. Patil): As you rightly pointed out, the scope of the Bill is very limited . . .

Mr. Speaker: Whether you should mop off this or not.

Shri S. K. Patil: On the 25th October, when this Ordinance was promulgated and the cane price was allowed to be raised to Rs. 1-10-0, on that day, there were stocks of sugar with the mills and they could have made this money, having contributed nothing for it. Therefore, Government wanted to wipe out that money, because that is a gain to the national exchequer, which would have otherwise gone to quarters which the hon. Member would not like. That is the scope of the Bill and nothing more. On the question of constitutionality also, if this amount was allowed to go, this question would not have come up, because so far as the price of cane was concerned, that was not the subject-matter of any legislation.

Mr. Speaker: The simple point is, this only relates to the price that ought to be fixed or the excise duty that has to be recovered from the stocks already there. It does not relate to the stocks that may come hereafter; they will be sold at the higher price which is now fixed on account of the increase in the price of sugarcane. We are not going into the question whether the higher price is adequate or not, whether it is right or wrong. Hon. Members may or may not agree in regard to that. Sugar is in stock. If they are allowed to sell it at the new increased price, the grower who sold the cane to them

does not get a pie. The consumer loses. In between the sugarcane factory-owners, whom it is not the intention of the Opposition to enrich, will get enriched at the cost of the consumer on the one side and with no profit to the grower on the other. The simple point is, does the hon. Member want that notwithstanding the fact that the cane-grower does not get a pie in regard to those stocks, the consumer must lose and the factory-owners should gain?

Shri Bimal Ghose: If the sugar price and the cane price have been increased then there will be no question of the excise duty.

Mr. Speaker: He does not want the price of sugar to be increased.

Shri Vajpayee (Balrampur): That is the point. Why the price of sugar has been increased? There is nothing about it in the Bill.

Mr. Speaker: For the future?

Shri Vajpayee: Simultaneously.

Mr. Speaker: Very well. Let him finish.

श्री खुशवक्त राय : यह तो मैं आपको बता ही चुका हूं । शूगरकेन की प्राइस के बारे में स्टेटमेंट आफ ओबजेक्टस एंड रीजंस को अगर मैं आपके सामने पढ़ दूं तो आपको बात बिलकुल स्पष्ट हो जायगी ।

Mr. Speaker: I only wanted to know one thing. When was this promulgated?

Shri S. K. Patil: On the 25th of October.

Mr. Speaker: The higher prices have been ruling since then?

Shri S. K. Patil: A large quantity of sugar was lying with the mills, and the mills would have made a profit out of the difference of Rs. 2|-. Therefore, this measure is to wipe out that profit. As you have rightly put it, it will give no advantage to the cane-grower or to the consumer. That is why it was wiped out.

Mr. Speaker: I would like to understand the position. Since the date of promulgation of the Ordinance, up to this date, they have been disposing of their stocks at the higher prices, and they have got the benefit.

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): Yes Sir.

Mr. Speaker: So far as the future is concerned, hon. Members may move a resolution whether the future price ought to be kept in check or not. So far as the period up to this time is concerned, are they to be allowed to walk away with the money?

Shri Bimal Ghose: This Bill is for the imposition of duty on sugar that was in stock at that particular time. If we disapprove of this amendment, then the price of sugar will not be raised and the sugar manufacturers will not gain.

Mr. Speaker: What happens to the period between October to this day?

Shri Bimal Ghose: The Government policy has been wrong.

Mr. Speaker: I am only trying to consider whether you are entitled to say, or I am bound to allow the discussion of that. The main point is this: what happens to the extra price that the sugar factory owners have obtained during this period?

Shri Braj Raj Singh: Since you are going to give a ruling on the scope of the discussion, may I submit that the whole policy of the Government has been that when they fix the price of sugarcane per maund, they also fix price of sugar per maund? If they did not want to fix the price of sugar per maund, there was no necessity to promulgate any Ordinance on the 25th of October. The price of sugar-cane could be increased without any increase in the price of sugar that is the contention. So, that may be evident.......

Mr. Speaker: What happens to the period in between? Let me divide it into two portions.

Shri Bimal Ghose: I could see your point. But the Bill which we are discussing refers to the future.

Mr. Speaker: In between what is to happen regarding this money?

Shri S. K. Patil: The position is this. Under the orders of the Government of India all stocks of sugar are to be kept by the mills and account of it submitted month after month to the Government. Not an ounce of sugar could be lifted without the orders of the Government. Since the price of cane was raised from Rs. 1|7|- to Rs. 1|10|- for the future stocks they have to pay the new price. But what happens to the stocks that are in the possession of the mills when the stocks go out? They will take the same price. That means that money will go into the pockets of the mill-owners to which they were not entitled to. The Ordinance only refers to that. The Ordinance would not have come even if we have to raise the price of sugar to any limit. An Ordinance was not necessary for that. The Ordinance has come because we want to mop up the money which will otherwise go to the mill-owners for no reasons whatsoever. Therefore, all these other questions, although relevant otherwise, do not arise out of the legislation that is before the House.

Shri Braj Raj Singh: May I read a portion of the Statement of Objects and Reasons? It states:

> "In order to stimulate production of sugar during the current season Government decided to increase the price of sugar-cane. Simultaneously the ex-factory price of sugar was also increased in proportion to the increase in cane price, by Rs. 2.52 per cwt. As the sugar produced out of cane purchased at the old cane price would have got an unintended benefit of the enhanced price, it was decided to mop up these profits for the public exchequer, by promulgation of an Ordinance."

There we agree that it should have been mopped up. It is a good thing. But, as regards the Bill, it is not necessary to increase the price of sugar.

Mr. Speaker: My trouble is this. We will assume that this Ordinance is repealed, not with retrospective effect, and this Bill is also thrown out. Would it have any effect of reducing the higher prices?

Shri S. K. Patil: No. What would happen is that about a crore of rupees that we have collected would go back to the mill-owners.

Shri Vajpayee: How can the money which you have collected go back?

Mr. Speaker: Let us be clear about it. It is not this Ordinance, or Bill, that empowers the Government to increase the cane price or the sugar price. The increase in cane-price or sugar price is not by virtue of this Ordinance, or by virtue of this Bill. It is done independently of this Bill, under another provision of law. Let us assume that the Ordinance is repealed, and the Bill is also not passed. That will not affect the sugar prices. Hon. Members have no objection to the sugar-cane prices being increased. They evidently object to the price of sugar being increased. Of course, I can allow full discussion of this. But even if they throw out the Bill, would the price of sugar that has been fixed go down?

Shri S. K. Patil: Nothing will happen.

Mr. Speaker: So far as this Bill is concerned, it is not under any of the provisions of this Bill that the price of sugar is increased.

Shri Bimal Ghose: But you will realise that the reason for bringing this Bill is that the sugar prices have increased.

Shri S. K. Patil: No.

Shri Bimal Ghose: It will follow consequently. Then the Government will not increase the price of.....

Mr. Speaker: Let us be clear of the position first. The sugar-cane price, or the sugar price is increased by

virtue of another Act, or by virtue of some authority vested in the Central Government, which is independent of the Ordinance. In view of having raised the sugarcane prices, hon. Member feel that sugar prices automatically need not be increased. Then, this money need not be allowed to go into the pockets of the mill-owners. This Bill is intended to recover a portion of the money that goes into the pockets of the mill-owners, and I think the hon. Members opposite are in full agreement with that. But they are under the impression that if this Bill is thrown out, and the Ordinance is repealed, the sugar price also will go down.

Shri S. K. Patil: It will not.

Mr. Speaker: This can be argued at any length of time, and I can allow five hours of our time to be spent on this matter. You may or may not approve of this Bill, but it will not affect the price of sugar. The only thing is that if they throw out this measure, more money will go into the pockets of the sugar-mill owners, which is not their intention. They will indirectly be helping, the sugar factory-owners, who will make a profit out of it.

Shri A. M. Thomas: Perhaps that is their objective.

Shri Bimal Ghose: What you say, Sir, is technically correct. But taking into consideration all the points, you may fix a time-limit.

Mr. Speaker: I have the least objection to give more time to hon. Members to speak on this. The food debate is not yet concluded, and I will allow hon. Members to raise the matter of sugar prices also in the food debate, if necessary. Let them say whatever they want. I will allot an hour or two, and those who are interested may say that the sugarcane prices or sugar prices ought to be increased or not, as part of the food debate.

Shri S. K. Patil: We have not replied to the food debate. I can also explain at that time whether we are bound to raise them. I am now merely confining myself to the constitutional position of this particular issue. Even if this is not passed, it will not affect the price.

Mr. Speaker: So, even if the Bill is thrown out, even if the Ordinance is repealed, the sugar price will continue and the new price will be in force.

Shri S. K. Patil: It will only mean that we have to give back the illegal recovery of about a crore of rupees.

Shri Braj Raj Singh: No.

Mr. Speaker: That is not the fear. Government has never given back.

Dr. B. Gopala Reddi: If it is illegal, we have to repay.

Mr. Speaker: What will happen is that for the stock which is still there and which has not been released those people will walk away with the higher price. There will be thus discrimination between one set of sugar factory owners and another set. Hon. Members are trying to favour those other people who have walked away with the money. I am only saying that that will be the consequence, which they do not intend. Therefore continuing this debate on the price of sugar will lead us nowhere.

Shri Braj Raj Singh: They are incidental matters, sugarcane price, sugar price and everything.

Mr. Speaker: There are many good matters which ought to come up before this House. This is one of such important matters. I would advise hon. Members not to refer to this matter. They can say incidentally that they do not agree with the increase in the price of sugar and that it does not naturally follow from the increase in the price of sugarcane. Whoever may raise his voice against it will stop at

[Mr. Speaker.]

that and proceed to the question as to whether we ought to refund this money or impose it and recover from the others too. So far as the matter of increase in the price of sugar is concerned, I will allow an opportunity to hon. Members to raise this matter during the food debate and the hon. Minister will reply to it.

Shri Bimal Ghose: Can I not say that there should have been no necessity for the excise duty on sugar being increased, but sugarcane price should have been increased more so that the sugar mill owners would not have got more?

Shri Braj Raj Singh: That is exactly the case I am going to put forward. There was no necessity for increasing the price of sugar with the increase in the price of sugarcane and there was no necessity for such a Bill. That case can be put forward and argued in this House.

Mr. Speaker: Only with respect to the existing stock. The excise duty is not to be there permanently.

Shri Braj Raj Singh: There is some misunderstanding. Perhaps the point was not caught. If the price of sugar had not been increased, there would have been no necessity for this Ordinance coming into force. Because sugarcane price was increased, Government also thought it fit to increase the price of sugar and the necessity of an Ordinance arose. Our case is that although it was good that the price of cane was increased, there was no consequent necessity for the increase in the price of sugar. That was wrong on the part of Government to do. So the necessity for all this discussion on the Ordinance comes in.

Raja Mahendra Pratap (Mathura): May I also submit one word? I am not allowed to speak. My great objection is what the objection of the hon. Prime Minister was that there should not be too much centralisation. We are making laws. Why do we not allow the sugarcane growers and the millowners to settle their questions among themselves? In every case we should not centralise. What I have been pointing out from time to time is that we burden too much our people by making laws. We say that the Government is of the people for the people. If it is the Government of the people then let the people make their own laws for their own need.

Mr. Speaker: I would like to know one more thing. Will this excise duty that is imposed under this Bill apply only to the stocks that are still with the millowners and which have not been sold?

Shri S. K. Patil: The stocks were under the control of Government although they were in actual physical possession of the mills. Now, if we had not passed this Ordinance, then the sugar when it is let out from those mills, that is, sugar that was there before the price was raised, would also have sold for the same price and Government would have lost this money, only the millowners would have got it. And that is not the purpose.

Mr. Speaker: I would like to know whether this additional excise duty will be operative for the new sugar that is produced.

Shri S. K. Patil: No. It will only be for that stock.

Dr. B. Gopala Reddi: It is 1.9 lakh tons.

Mr. Speaker: Now the point is clear. The question is whether I should allow a general discussion about the increase in price of sugar, that is, the price that has been fixed so far as sugar is concerned.

Shri Bimal Ghose: That is not the question. The question is whether the Ordinance was promulgated wisely or not. We have a right to say that it was a wrong policy. Whether it should be given back or not......

Mr. Speaker: The simple question, therefore, is.... (*Interruption*). The price of sugar and sugarcane had increased not under the authority of the Ordinance or the Bill but independently. The Government has got the power to increase it under a previous Statute or otherwise. Once that has been done, the only question is whether the sugar factory owners or the stockists who have got that sugar should be allowed to take away the additional profit which accrues when it is sold. It is a windfall for them. Whether they should take it away without returning it to the sugarcane growers or whether they should recover it from the consumer is the question. The excise duty is intended to mop it off. By passing this Bill, this excise duty is not going to continue on any sugar that is produced hereafter. The question whether the increase in the price of sugar ought to have been made or ought not to have been made is not relevant to this Bill inasmuch as the passing of this Bill, or even if the Bill is thrown out, will have no effect on the increase that has been made in the price of sugar. That will stand.

Under these circumstances I direct that so far as this discussion of this Bill or the Ordinance is concerned; it is limited in scope. That will be limited only to the point as to whether excise duty should be imposed and the additional money should be recovered or whether Government ought not to do so and allow the sugar factory owners to walk away with it or the stockists should walk away with it.

So far as the general question relating to the increase in the price of sugar is concerned, I find that hon. Members are interested in it. It may be a matter which has to be discussed. I will allow them ample opportunity during the food debate which has not yet concluded. After the debate is over the hon. Minister will reply and give reasons for justifying it. If the House comes to a different conclusion, certainly the expression of opinion in the House in a large measure must influence the Government to take a decision or alter its view.

Let us now proceed and dispose it of.

Shri Mahanty (Dhenkanal): In that case the time for the food debate may kindly be extended by an hour or so.

Mr. Speaker: I will do so. Now hon. Members will dispose of this matter quickly.

Shri Prabhat Kar (Hooghly): We cannot refer to the background of the promulgation of the Ordinance if you do not allow discussion on that. Once you allow discussion of the background then the question of increase in the price of sugar will come in.

Shri Braj Raj Singh: It is incidental.

Mr. Speaker: Whoever raises the point that he is not in favour of the increase in the price of sugar will go into its details during the food debate. They may mark their protest against the increase in the price of sugar which has been brought about due to the increase in excise duty.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I have one suggestion to make.

Mr. Speaker: I will allow an hour or half an hour.

Shri S. M. Banerjee: Suppose the discussion finishes by three o'clock. The discussion on the Pay Commission's report is at 4 o'clock. You have to fix time for this discussion. How long are you going to allow this discussion so that we can inform others?

Mr. Speaker: We will finish it quickly.

Dr. B. Gopala Reddi: As far as the Bill is concerned, there is no objection to the Bill at all.

Mr. Speaker: Hon. Members must be clear in their minds. If they pass the Bill, they will take away a portion of the sugar factory owners' profit. If they throw out the Bill.....

Shri Braj Raj Singh: We are not going to throw it away.

Mr. Speaker: In spite of this the Government may continue to allow an increase in the price of sugar. This would not have any effect. Hon. Members will have an opportunity to speak. I will allow them to speak during the food debate.

Shri Braj Raj Singh: There is very little time for the food debate.

Mr. Speaker: I am going to allow. Why should he say that he cannot? Let us therefore confine ourselves to the exact position in regard to this. Hon. Members will have an opportunity. Sugar is also food. I will allow them an opportunity.

Shri Vajpayee: There is nothing objectionable in this Bill.

Dr. B. Gopala Reddi: Then the Bill may be passed.

Mr. Speaker: Then the question is:

"That the Bill be passed."

श्री खुशवक्त राय: आपने यह निर्णय तो दे दिया मगर मेरी बात नहीं सुनी . .

अध्यक्ष महोदय: बाद में आपको मौका दे दूंगा ।

श्री खुशवक्त राय: जब सरकार कभी कोई आर्डिनेंस निकालती है तो नियम ७१ के मुताबिक मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय: वह स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है ।

श्री खुशवक्त राय: उस स्टेटमेंट में जो सब बातें लिखी हुई हैं उनके बारे में मैं बहस करना चाहता हूं ।

Mr. Speaker: परवाह नहीं । The substance of the Ordinance must be looked into, whatever he may state.

Shri Khushwaqt Rai: Not only the substance, but the causes leading to the promulgation of the Ordinance.

Shri S. K. Patil: No causes.

Shri Khushwaqt Rai: The statement says:

> "As an incentive for increased production of sugar during the season 1959-60, it was decided by Government in October, 1959, to enhance the price of sugarcane. Simultaneously the ex-factory price of sugar was also proposed to be enhanced in sympathy with the increase in cane price by Rs. 2.52 per cwt."

As a result of the proposed increase in sugar prices, the sugar factories have made an inordinate profit which amount this Government wanted to mop up by this Ordinance. All these things are interconnected.

13 hrs.

Mr. Speaker: They are mere statements. I have already stated that they are mere statements. There is no good pursuing this matter. I do not want to shut out any discussion. This won't lead us anywhere. The hon. Member will have the satisfaction of having said all this. What next?

Shri Braj Raj Singh: There is no difference about the purpose.

Shri Bimal Ghose: In spite of whatever we may say, the Government get what they want. What next?

Mr. Speaker: It is not right. Even the Opposition should persuade all the Congress Members here on the side of the Government to accept their suggestion here, it won't have any effect. It is not a decision of the House reducing the price of sugar.

Shri Braj Raj Singh: No.

Mr. Speaker: They will have an opportunity to persuade the House tomorrow to advance all arguments. I am not shutting them out.

Shri Heda (Nizamabad): There is one pertinent point about the method

of increasing the sugarcane prices and fixing the price of sugar. The very method, I think, can be discussed under this Bill. Had there been a more scientific and more rational method of fixing the prices, the need for all this contingency would not have arisen. Therefore, I think the House may be able to discuss the method of fixing the sugarcane prices and sugar price.

Mr. Speaker: That would come tomorrow.

Shri Vajpayee: Our difficulty is, the price of sugarcane or the price of sugar is not fixed in consultation with this House. This is only the occasion when we can express our resentment against the manner in which the price of sugar is fixed.

Mr. Speaker: Instead of moving an adjournment motion and provoking me to dismiss it, if the hon. Members had said that these are the points and sugar prices ought not to have been increased, I would have allowed a discussion for a couple of hours or 2½ hours.

Dr. B. Gopala Reddi: Instead of attacking the Ordinance or the Bill, they could have come forward with a straightforward motion.

Mr. Speaker: Order, order. If they want two hour or two and a half hour discussion, I am prepared to allow on the increase in sugar prices tomorrow or the day after before we disperse.

Shri Khushwaqt Rai: Both sugarcane and sugar.

Mr. Speaker: All right. Sugarcane and sugar are intimately connected. I am prepared to allow a discussion.

Shri S. K. Patil: Why not increase the time for the Food debate which is a part of it rather than having it in two?

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): You won't be allowing the Members to speak more than 15 minutes. He will have to cover sugar and food. It will be better if a separate time is given.

Mr. Speaker: If the hon. Members do not raise this matter in the debate, I will not increase the time by 1½ hours. I will reserve it for a debate.

श्री खुशवक्त राय : मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह तय है जैसा कि आपने कहा कि शुगरकेन और शुगर प्राइस के बारे में दो घंटे का समय दिया जायेगा ?

Mr. Speaker: If they do not raise this point in the Food debate. . . . .

श्री खुशवक्त राय : तो अध्यक्ष महोदय . . . .

Mr. Speaker: . . . .I will all the same. He may conclude now. What more has he to say?

श्री खुशवक्त राय : श्रीमन, आपने यह कहा कि अगर यह बिल थ्रो हो जाय तो उसका क्या असर होगा तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह बिल अगर थ्रो हो जाय तो यह मिनिस्ट्री खत्म हो जायगी और सारा केबिनेट खत्म हो जायगा । इसलिए श्रीमान ऐसी बात नहीं है कि अगर बिल थ्रो हो जाय तो उसका क्या होगा । श्रीमन, मैंने आपको शुगरकेन के बारे में भी बता दिया और थोड़ा सा यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्य मंत्री जी हैं उन्होंने उसका हिसाब लगवाया था कि शूगर का क्या मूल्य आता है तो उस हिसाब से उन्हें यह पता चला कि ३३ रुपये २५ नये पैसे और ३३ रुपये ३४ नये पैसे की बनती है, ३४ रुपये की शूगर बन गयी तो उस ३४ रुपये की जो शूगर बनी उस में फिर मूल्य बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी ? और अगर यह शूगर का मूल्य नहीं बढ़ता तो यह आर्डिनेंस फिर नहीं आता और इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती । श्रीमन, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक्सचेकर को क्या अधिकार है कि वह उस रुपये को

[श्री खुशवक्त राय]

अपने पास रखे । गन्ना काश्तकारों ने दिया और काश्तकारों के उस गन्ने से चीनी बनी जिसका कि आपने मूल्य बढ़ाया और यह जो चीनी के दाम आपने बढ़ाये तो उसका लाभ आप उस गन्ने के काश्तकार को नहीं देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अन्याय है क्योंकि जब आपने चीनी के दाम बढ़ाये तो गन्ना जिससे कि वह चीनी बनी उसका लाभ गन्ना उत्पादकों को भी मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार तो वही चीज कर रही है जैसे दो बिल्लियों में झगड़ा हुआ और बन्दर ने बन्दर बांट करके सारी रोटी हज्म करनी शुरू कर दी और तमाम रोटी खा गया ।

श्रीमन, चूंकि आपने कह दिया है कि आप इस पर फिर डिबेट एलाऊ करेंगे इसलिए मैं और अधिक न कह कर बैठ जाता हूं ।

Mr. Speaker: The hon. Minister.

Shri Braj Raj Singh: A few minutes, Sir.

Mr. Speaker: Five minutes each.

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेंस की भावना और उद्देश्य का मैं स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही मैं ने इस सदन में कई बार इसका विरोध किया है कि सरकार को अपने आर्डिनेंस बनाने की जो ताकत है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उसके पीछे उद्देश्य यह रहा है कि आर्डिनेंस बना कर सरकार सदन को विश्वास में नहीं लेना चाहती है लेकिन जिस वक्त यह आर्डिनेंस बना उस वक्त मैं समझता हूं कि सरकार के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वह खुद आर्डिनेंस बना कर और जो रुपया सरकार की गलत नीति के कारण शुगर फैक्टरीज के मालिकों को मिल रहा था वह रुपया अपने खजाने के लिए लेती और इसलिए मैं इस आर्डिनेंस का स्वागत करता हूं लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आर्डिनेंस बनाने की ताकत का इस्तेमाल सरकार को कम से कम करना चाहिए और हो सके तो ऐसा नियम बनाना चाहिए कि आर्डिनेंस बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठे ।

असल में जहां तक कि इस गन्ने की कीमत को बढ़ाने का सवाल है और उससे सम्बन्धित जो चीनी की कीमत बढ़ाई गई और जिसके कि कारण यह आर्डिनेंस बनाना पड़ा तो वह सवाल ऐसा नहीं था जो कि २५ अक्तूबर को पैदा हो गया था । वह तो उससे पहले बहुत दिनों से चला आ रहा था । आखिर गन्ने की कीमत बढ़ाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के काश्तकार पिछले दो, तीन साल से लगातार आन्दोलन करते रहे हैं, सरकार के सामने मांगें पेश करते रहते हैं लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने उस पर कोई उचित ध्यान नहीं दिया और सरकार हमेशा यह कहती रही कि यह तो राज्य का प्रश्न है और इसलिए हम अर्थात् केन्द्रीय सरकार उस पर कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है और जब उन्होंने विचार किया तो ऐसे वक्त में किया जब कि सदन बैठ नहीं रहा था और जब कि लोक-सभा का अधिवेशन हो नहीं रहा था । इसलिए मैं तो समझता हूं कि अगर सरकार पहले से सतर्क रहे तो उसे भविष्य में इस प्रकार के आर्डिनेंस को बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । पहले से इस बात को देखती रहे कि क्या जनता की मांगें हैं और क्या जनता की तकलीफें हैं और उन तकलीफों को जब हमारा सदन बैठा रहता है तो क्या उसके सामने नहीं ला सकते हैं । मेरा ख्याल है कि इनको सदन के सामने लाया जा सकता है और अगर ऐसा सरकार करना शुरू कर दे तब फिर किसी आर्डिनेंस के बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इस आर्डिनेंस के भी बनाने की जरूरत न पड़ती । अब प्रश्न यह उठता है कि कहीं यह गलतफहमी न पैदा हो जाय उन लोगों के प्रति जिन्होंने कि आर्डिनेंस का विरोध करते

के लिए प्रस्ताव किया है कि उनका शायद यह आशय है कि आर्डिनेंस के पीछे जो भावना और उद्देश्य है उसका वे विरोध कर रहे हैं तो मैं यह चीज साफ कर देना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है और किसी की भी ऐसी भावना नहीं है। सरकार की गलत नीति के कारण जो मिलओनर्स ज्यादा मुनाफा उठाने वाले थे उसको वह रोकती लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब गन्ने की कीमत बढ़ाई तो क्या चीनी की कीमत बढ़ाने की जरूरत थी ? मेरा तो कहना है कि गन्ने की कीमत बढ़ने से चीनी की कीमत बढ़ाने का कहीं कोई प्रश्न नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया है कि मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखूं हालांकि इससे सभी मामले सम्बन्धित हैं। मैं यह सिद्ध करने को तैयार हूं कि २ रुपये प्रति मन गन्ने की कीमत देने के बाद भी आपको ३२ रुपये से ज्यादा शक्कर की कीमत देने की जरूरत नहीं है और उसी में उनका सारा मुनाफा आ सकता है। आश्चर्य तो यह है कि सरकार की तरफ से यह देखने की कोशिश नहीं की जाती है कि हम जब गन्ने की कीमत बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ शूगर की कीमत बढ़ाने की जरूरत है भी या नहीं, कोई इस प्रश्न को देखता ही नहीं है।

Mr. Speaker: I have fixed the sugar discussion for Monday or Tuesday as the Minister may agree. Therefore, hon. Members may not discuss sugar and sugarcane prices. I have definitely fixed; there are two half hour discussions on Monday and Tuesday. They have been postponed from the previous session. I will allow them opportunities to raise these points, since this seems to be a very important matter agitating the minds of the hon. Members here. Although it is said there is a strike and so on, I do not allow the strike to influence my mind; I am merely carried by hon. Members' interest in the matter. I will allow this matter to be brought up on Monday. I will allow ample opportunity to Shri Braj Raj Singh and others.

श्री मु० तबक्त राय : मुझे भी मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी, सब को मिलेगा।

श्री ब्रजराज सिंह : खत्म करने से पहले मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं। इस बात की ओर मैं सरकार का विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की हड़ताल हो रही है। मैं तथ्यों में नहीं जाना चाहता। सरकार की सूचना है कि ६ मिलों में हड़ताल है और हमारी सूचना है कि ६३ मिलों में हड़ताल है। मेरे मित्र श्री शिब्बन लाल सक्सेना का, जो कि इस माननीय सदन के एक माननीय सदस्य हैं, आज ही एक तार आया है जिस में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की ६६ मिलों में से ६३ में हड़ताल है। यह मामला विवादास्पद हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न ऐसा है कि जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना पैदा करने वाले ३५ लाख परिवारों का सम्बन्ध है। इस पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाना चाहिए। आपने निर्णय किया है कि इस प्रश्न पर सोमवार को बहस होगी। मैं नहीं चाहता कि यह हड़ताल एक मिनट भी ज्यादा चले। मैं चाहता हूं कि सरकार इस को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाये। जहां तक हमारा सवाल है हम इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं समझते। सरकार चाहती है कि उत्पादन का नुकसान न हो और हम भी यही चाहते हैं। इसलिए मैं आशा करूंगा कि सरकार इस प्रश्न पर सहानुभूति से विचार करेगी और बहस समाप्त होने के साथ ही ऐसा कदम उठायेगी कि हड़ताल समाप्त हो और चीनी के उत्पादन में कमी होने की कोई आशंका न रहे।

Dr. B. Gopala Reddi: As far as my Bill is concerned, there seems to be no objection either to the issue of the ordinance or to the Bill itself replacing it. The only point that was raised was whether the ordinance was at all necessary and whether Government should have exercised their power to issue the ordinance.

After all, we were anxious to help the cultivator by enhancing the price of sugarcane, and that has been done. There was a persistent demand from U.P. and Bihar also that the sugarcane prices should be enhanced. In deference to that public pressure as it were, and because the U.P. Government was also thinking that there was a case for enhancing the sugarcane prices, Government thought it should be enhanced by three annas, and consequently the sugar price was enhanced, but that is a different matter. When that was done, the factory people had 1·9 lakh tons with them, and we wanted they should not get unmerited profit out of these stocks, and therefore we enhanced the central excise duty by Rs. 2·52 per cwt. There is no objection to that, and I am glad this Bill has the unanimous approval of this House.

With regard to the other matter, the hon. Food Minister and the Deputy Minister will deal with it, as to whether there is a case for enhancing the sugar price consequent on the increase in the price of sugarcane.

Mr. Speaker: That will be discussed on an independent motion, notice of which has been given by Shri Braj Raj Singh, Shri Khushwaqt Rai and others. I have allowed it.

Even today hon. Members need not go away, those who are interested in taking part in the discussion on sugar and sugarcane prices. I believe the Tariff Bill may not take much time. I will call them after the Tariff Bill and allow them an opportunity immediately, since the next item is only at 4 O'clock.

Shri V. P. Nayar (Quilon): What is the time fixed for the Bill?

Mr. Speaker: There is no time fixed. It may not take more than half an hour.

Shri V. P. Nayar: I will myself take two hours if I am allowed.

Mr. Speaker: The question is:

"This House disapproves of the Sugar (Special Excise Duty) Ordinance, 1959 (Ordinance No. 2 of 1959) promulgated by the President on the 25th October, 1959".

The motion was negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill to provide for the imposition of a special duty of excise on certain sugar, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

"That Clauses 1 to 5, the Enacting Formula and the Long Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1 to 5, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

Dr. B. Gopala Reddi: I beg to move:

"That the Bill be passed".

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.16 hrs.

INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

The Minister of Industry (Shri Manubhai Shah): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Indian Tariff Act, 1934, be taken into consideration."